भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या2739
जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है ।
20 अग्रहायण, 1946 (शक)

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार

2739.श्री लुम्बा राम:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-वाणिज्य, ई-कौशल, ई-मौसम संबंधी सूचना और ई-शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है;
(ख) क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत जालौर और सिरोही जिलों की सभी ग्राम पंचायतों, सरकारी विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ब्रॉडबैंड सुविधाओं सो जोड़ने का प्रस्ताव है;
(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी ग्राम पंचायतो, सरकारी विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को इससे जोड़ा गया है;
(घ) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार से लोगों को होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम को व्यापक रूप से सुधार करने और इसमें विस्तार करने के लिए क्या विभिन्न उपोय किए जा रहे हैं?

उत्तर
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ):डिजिटल इंडिया पहल से भारत में इंटरनेट तक पहुंच में काफी तेजीआई है और इससे विकास को बढ़ावा मिला है। भारत सरकार ने डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था इस कार्यक्रम का सामान्यतया लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियों से प्रत्येक नागरिक का जीवन को बेहतर बनें, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हो तथा भारत में निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हों।

डिजिटल इंडिया की भारतनेट जैसी पहलों के कारण इंटरनेट सुविधा तक पहुँच का तेजी से विस्तार करने में काफी मदद मिली है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। इसके परिणामस्वरूपदेश भर में इंटरनेट की पहुंच और उपयोग में काफी वृद्धि हुई है । पिछले दशक में भारत में इंटरनेट सुविधा तक पहुंच में बहुत वृद्धि हुई है। हाल के आँकड़ों के अनुसार, भारत की गणना दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट बाज़ारों की जाती है, जहाँ 94 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं (स्त्रोत- 21 नवम्बर 2024 की दूरसंचार सदस्यता रिपोर्ट)।

दूरसंचार विभाग सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को लागू कर रहा है। भारतनेट परियोजना के तहत बनाया गया बुनियादी ढांचा एक राष्ट्रीय संपत्ति है, जो बिना किसी भेदभाव के सेवा प्रदाताओं के लिए सुलभ है।

दिनांक 04.08.2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,64,554 ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विस्तारित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, जिसमें ऐसी मौजूदा ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं

जो पहले से ही सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हैं। परियोजना के अंग के रूप में, ब्रॉडबैंड या इंटरनेट सेवाओं कीकनेक्टिविटी को अंतिम छोर तक पहुँचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई या किसी अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग किया जाएगा। अन्य उपयुक्त तकनीकों में फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन तथा सरकारी संस्थाओं जैसे कि स्कूल, अस्पताल, डाकघर, पुलिस स्टेशन आदि में लीज्ड लाइनें उपलब्ध कराना शामिल हैं।

अक्टूबर, 2024 तक देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,283 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है। राजस्थान राज्य में 8,997 ग्राम पंचायतों (जालौर की 274 ग्राम पंचायतों और सिरोही जिले की 162 ग्राम पंचायतों सहित) को सेवा के लिए तैयार किया गया है।

15वें वित्त आयोग के कार्यकाल अर्थात 2021-22 से 2025-26 के दौरान अगस्त 2023 में सरकार द्वारा 14,903.25 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंज़ूरी प्रदान की थी।इस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार करने के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

(i) इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(ii) डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना/प्लेटफार्मों और डिजिटल समावेशन के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना।

(iii) शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों तथा सरकारी संस्थाओं को उच्च गति कनेक्टिविटी प्रदान करना।

(iv) इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर में विनिर्माण क्षमताओं और आत्मनिर्भरता के विकास को बढ़ावा देना।

(v) आईटी क्षेत्र में भारत की ताकत, विघटनकारी नवाचारों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए एक स्थायी सॉफ्टवेयर उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देना।

(vi) सुपरकंप्यूटिंग, क्वांटम प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे प्रमुख और अप्लाइड क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(vii) देश में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के कार्य में राष्ट्रीय स्तर पर रीयल टाइम साइबर सुरक्षा की तरह से स्थितिजन्य जागरूकता पैदा करना।

(viii) डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और कार्यसंव्यवहार में पारदर्शिता लाना।

****